

सहमति ज्ञापन (एम.ओ.ए.)

राजस्थान राज्य, मध्य प्रदेश राज्य

और

संघ सरकार के बीच में

संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना

MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

amongst

THE STATE OF RAJASTHAN,

THE STATE OF MADHYA PRADESH

and

THE UNION GOVERNMENT

on

**MODIFIED PARBATI-KALISINDH-CHAMBAL
LINK PROJECT**

05th December, 2024

New Delhi

**संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना पर
राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच
समझौता ज्ञापन (एम.ओ.ए.)**

पक्षकारों के नाम और पते

1. राजस्थान सरकार, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, जयपुर।
2. मध्य प्रदेश सरकार, जल संसाधन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. केंद्र सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।

I. प्रस्तावना

- क. जबकि भारत सरकार नदी अंतर्त्योजन संबंधी कार्यक्रम को राष्ट्रीय महत्व का मानती है और परियोजना अनुदान तंत्र के लिए तौर-तरीकों का पता लगाने/सुझाव देने के लिए कार्य करेगी ताकि परियोजना को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।
- ख. जबकि भारत सरकार तथा राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य बेसिन में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के एकीकरण सहित चंबल बेसिन की नदी अंतर्त्योजन के लिए सहमत हो गए हैं। संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल (एमपीकेसी) लिंक परियोजना के रूप में नामित यह लिंक परियोजना, देश में नदी अंतर्त्योजन की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) का हिस्सा होगी, जैसा कि नदी अंतर्त्योजन के लिए विशेष समिति (एससीआईएलआर) ने 13 दिसंबर, 2022 को आयोजित अपनी 20वीं बैठक में अनुमोदित किया था।
- ग. जबकि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ) ने दोनों राज्यों, नदी अंतर्त्योजन संबंधी कार्यबल और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के परामर्श से दोनों राज्यों के लाभ के लिए चंबल बेसिन में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है, जो 28 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में भारत सरकार, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के अनुसार है **(समझौता ज्ञापन की प्रति अनुलग्नक-1 पर संलग्न है)**। ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना के सभी घटकों को शामिल करते हुए

MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
AMONGST THE STATE OF RAJASTHAN, THE STATE OF
MADHYA PRADESH AND THE UNION GOVERNMENT ON
MODIFIED PARBATI-KALISINDH-CHAMBAL LINK PROJECT

Name & Addresses of Parties

1. Government of Rajasthan, Water Resources Department, Sinchai Bhawan Jaipur.
2. Government of Madhya Pradesh, Water Resources Department, Vallabh Bhawan, Bhopal.
3. Union Government, Ministry of Jal Shakti, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.

I. Introduction

- A. WHEREAS the Government of India considers the programme for inter-linking of rivers as of national importance and shall work out to find out/suggest modalities for project funding mechanism so as to enable to complete the project within the stipulated time frame.
- B. WHEREAS the Government of India and the States of Rajasthan and Madhya Pradesh have agreed for interlinking of rivers of Chambal basin including the integration of Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP) for the optimum utilisation of water resources in the basin. This link project named as the Modified Parbati-Kalisindh-Chambal (MPKC) Link Project, shall be part of the National Perspective Plan (NPP) of interlinking of rivers in the country, as approved by Special Committee for Interlinking of Rivers (SCILR) in its 20th meeting held on 13th December, 2022.
- C. WHEREAS National Water Development Agency (NWDA) in consultation with both the States, Task Force on ILR and Central Water Commission (CWC) have evolved a Comprehensive Plan for the optimum utilisation of water resources in the Chambal basin for the benefits of both the States in accordance with the tripartite MoU signed amongst the Government of India, the States of

व्यापक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट रा.ज.वि.अ, सीडब्ल्यूसी और दोनों राज्यों द्वारा प्रचलित दिशानिर्देशों और राज्यों के बीच बनी सहमति के अनुसार संयुक्त रूप से तैयार की जा रही है।

घ. और जबकि केंद्र सरकार, राज्यों के परामर्श से किए गए करार के अनुसार चंबल घाटी विकास परियोजना सहित चंबल बेसिन में जल के नियंत्रण तंत्र, जल लेखांकन और विनियमन के लिए दोनों राज्यों को शामिल करते हुए एक उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था सृजित करेगी। इस संस्था के संबंध में संघटन, विचारार्थ विषय और अन्य संबंधित मुद्दों पर बाद में उचित समयानुसार निर्णय लिया जाएगा।

II. अब, इसलिए संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पार्टियों द्वारा निम्नानुसार समझौता किया जाता है:

1.0 संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना में जल बंटवारा

1.1 संशोधित पीकेसी लिंक में जल बंटवारा, नियंत्रण बोर्ड में दो राज्यों के बीच बनी सहमति के अनुसार नियंत्रित होगा और दो राज्यों के बीच चंबल घाटी परियोजना पर मौजूदा अंतर-राज्यीय समझौतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, "सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए दिशानिर्देश, भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, 2010" और अंतर-राज्यीय नदियों में सिंचाई परियोजनाओं की योजना के लिए नीति आयोग के मानदंडों के अधीन होगा।

1.2 दोनों राज्य कालीसिंध उप-बेसिन और चंबल नदी की बायीं सहायक नदियों के जल को 75% निर्भरता से अधिक और 50% निर्भरता तक दोहन के लिए सहमत हैं, जो लागू मानदंडों, जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग और "सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, 2010" के नियोजन मानदंडों को पूरा करने के आधार पर निर्धारित मांग के अनुसार होगा। चंबल बेसिन के किसी अन्य उप-बेसिन में 75 प्रतिशत निर्भरता से अधिक जल के दोहन पर बाद में, दोनों राज्यों द्वारा सीडब्ल्यूसी के परामर्श से, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लिया जा सकता है। एमपीकेसी परियोजनाओं के लिए उनके हिस्से की मात्रा और इन उप-बेसिनों में उपयोग के अनुसार, जैसा कि **अनुलग्नक-II** (जल उपलब्धता का आकलन) और

Rajasthan and Madhya Pradesh on 28th January, 2024 in New Delhi (*Copy of the MoU enclosed at Annexure-I*). The comprehensive Detailed Project Report covering all the components of the Modified PKC link project duly integrated with ERCP, is under preparation jointly by NWDA, CWC and both the States as per the prevailing guidelines and the understanding reached between the States.

D. AND WHEREAS the Union Government, in consultation with the States, will create an appropriate institutional arrangement involving both the States for control mechanism, water accounting and regulation of water in Chambal basin including Chambal Valley Development Project in accordance with the agreement reached. The composition, terms of reference and other related issues in respect of this institution shall be decided later in due course.

II. NOW, THEREFORE IT IS HEREBY ENTERED INTO AGREEMENT BY THE PARTIES AS FOLLOWS FOR THE IMPLEMENTATION OF MODIFIED PKC LINK PROJECT:

1.0 WATER SHARING IN THE MODIFIED PKC LINK PROJECT

1.1 The water sharing in the Modified PKC link shall be governed as per the understanding reached between two States in the Control Board and without prejudice to the existing inter-State agreements on Chambal valley project between two States, subject to the prevailing "Guidelines for preparation of DPRs of Irrigation and Multipurpose Projects, Govt. of India, Ministry of Water Resources, 2010" and NITI Aayog norms for planning of irrigation projects in inter-State rivers.

1.2 Both the States hereby agree to harness more water of Kalisindh sub-basin and left tributaries of the Chambal river beyond 75 % dependability and upto 50% dependability as per demands assessed based on applicable norms, optimum utilization of water resources and fulfilling the planning norms of "Irrigation

अनुलग्नक-III (एमपीकेसी लिंक परियोजना के घटकों का विवरण) में दर्शाया गया है, दोनों राज्य चंबल के प्रत्येक उप-बेसिन में सहमत निर्भरता, कालीसिंध उप-बेसिन और बायीं सहायक नदियों में 50% निर्भरता और कुनो और पार्वती उप-बेसिन में 75% निर्भरता तक, जल का दोहन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

- 1.3 संशोधित पीकेसी लिंक के अंतर्गत परियोजनाओं/पथांतरण बिन्दुओं के विभिन्न स्थानों पर सकल यील्ड श्रृंखला, जो संबंधित राज्यों द्वारा आपूर्ति किए गए वास्तविक उपयोग आंकड़ों और सीडब्ल्यूसी के जी एंड डी स्थलों पर देखे गए प्रवाह आंकड़ों के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा आंकलित की गई है, उपर्युक्त स्थलों पर नेट यील्ड की भविष्य में गणना करने के लिए आधार आंकड़ा श्रृंखला होगी।
- 1.4 संशोधित पीकेसी लिंक के तहत, दोनों राज्यों के बीच 75 प्रतिशत निर्भरता पर कुनो और पार्वती उप-बेसिन में जल का समान आदान-प्रदान होगा। किए गए आकलन के अनुसार, राजस्थान के हिस्से से कुनो उपबेसिन में 116 एमसीएम के अधिशेष का उपयोग मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कुनो उप-बेसिन में किया जाएगा, जबकि राजस्थान द्वारा 75% निर्भरता पर जल की समान मात्रा का उपयोग पार्वती उप-बेसिन के मुक्त जलग्रहण भाग में मध्य प्रदेश के हिस्से से ईआरसीपी के लिए महलपुर बैराज से पथांतरण हेतु किया जाएगा। कुनो और पार्वती उप-बेसिनों में जल के अधिशेष और स्वीकार्य आदान-प्रदान के आकलन की समीक्षा, राजस्थान द्वारा पार्वती उपबेसिन और मध्य प्रदेश द्वारा कुनो उपबेसिन में परिकल्पित परियोजनाओं के पूरा होने के बाद और बाद में प्रत्येक पांच वर्ष में, सीडब्ल्यूसी के परामर्श से की जाएगी।
- 1.5 मध्य प्रदेश राज्य संशोधित पीकेसी लिंक के अंतर्गत पहचान की गई पाँच परियोजनाओं के माध्यम से ऊपरी चंबल बेसिन में अतिरिक्त जल (लगभग 450 एमसीएम) का उपयोग करेगा जो इन परियोजना स्थलों पर 75 प्रतिशत निर्भरता पर उपलब्ध जल के अनुरूप है। ऊपरी चम्बल में पाँच परियोजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश द्वारा उपयोग किए गए जल की समान मात्रा को सुनिश्चित करते हुए, प्रतिस्थापन आधार पर 75 प्रतिशत से अधिक सफलता दर पर कालीसिंध उप-बेसिन से गांधीसागर जलाशय में अंतरित किया

and Multipurpose Projects, Govt. of India, Ministry of Water Resources, 2010". The harnessing of more water in any other sub-basin of Chambal basin beyond 75 percent dependability can be decided later by both the States as per their requirements, in consultation with CWC. Both the States shall be free to harness water in each of the sub-basins of Chambal as per agreed dependability upto 50% dependability in Kalisindh sub-basin and left tributaries and at 75% dependability in Kuno and Parbati sub-basins with quantum of their share for MPKC projects and uses in these sub-basins as indicated in **Annexure-II** (Assessment of Water Availability) and **Annexure-III** (Details of Components of MPKC link project).

- 1.3 The gross yield series at various locations of projects/diversion points under Modified PKC link, assessed by Central Water Commission based on the actual utilization data supplied by respective states and the flow data observed at G&D sites of CWC, shall form the base data series for further calculating net yield at above locations.
- 1.4 Under the Modified PKC link, there shall be equal exchange of water in Kuno and Parbati Sub-basins at 75 percent dependability between the two States. As per assessment made, the surplus of 116 MCM in Kuno Sub-basin from Rajasthan portion shall be utilized by the State of Madhya Pradesh in Kuno sub-basin, while an equal quantum of water at 75% dependability shall be utilized by Rajasthan for diversion from Mahalpur barrage for ERCP from share of Madhya Pradesh in the free catchment portion of Parbati sub-basin. The assessment of surplus and admissible exchange of water in Kuno and Parbati sub-basins shall be reviewed in consultation with CWC, after completion of projects envisaged in Parbati sub-basin by Rajasthan and in Kuno sub-basin by Madhya Pradesh and subsequently every five years.
- 1.5 The State of Madhya Pradesh shall utilize additional water in Upper Chambal basin (about 450 MCM) through five nos. of projects identified under the Modified PKC link corresponding to water available at 75 percent

जाएगा। कालीसिंध उप-बेसिन से गांधीसागर जलाशय तक संपूर्ण जल अंतरण प्रणाली (बैराज, पंपिंग स्टेशन और जल परिवहन प्रणाली सहित) की पूंजी लागत, संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना का हिस्सा होगी। कालीसिंध से गांधीसागर जलाशय तक जल अंतरण की ओ एंड एम लागत (बिजली लागत सहित) मध्य प्रदेश द्वारा वहन की जाएगी। ऊपरी चंबल में मध्यप्रदेश की पांच परियोजनाओं को, कालीसिंध से गांधीसागर तक जल के पथांतरण की व्यवस्था होने के बाद ही संचालित किया जाएगा ताकि मौजूदा चंबल घाटी विकास परियोजना से, दोनों राज्यों केलाभ प्रभावित न हों। ऊपरी चंबल बेसिन और कालीसिंध उप-बेसिन में जल के आदान-प्रदान की समीक्षा, ऊपरी चंबल बेसिन में परियोजनाओं के पूरा होने के बाद और बाद में हर पांच साल में, सीडब्ल्यूसी के परामर्श से की जाएगी। कालीसिंध नदी पर बैराज और कालीसिंध से गांधीसागर तक जल के डाइवर्जन के लिए जल संवाहक प्रणाली का संचालन और रखरखाव, चंबल बेसिन में जल के नियंत्रण तंत्र, जल लेखांकन और विनियमन के लिए बनाई जाने वाली संस्था द्वारा किया जाएगा।

- 1.6 संशोधित पीकेसी लिंक के किसी भी परियोजना स्थल पर नेट जल उपलब्धता का आकलन करते समय, मौजूदा, चल रही और विचारित परियोजनाओं, की आवश्यकताओं और प्रत्येक राज्य के परियोजना स्थल के अपने क्षेत्र में अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम की आवश्यकताओं पर विचार करने के अलावा, दोनों राज्यों द्वारा पर्यावरणीय प्रवाह के लिए 75% निर्भरता पर मानसून यील्ड का 10 प्रतिशत और उस स्थान पर गैर-मानसून प्राकृतिक यील्ड का 100 प्रतिशत, आरक्षित रखा जाएगा।
- 1.7 संशोधित पीकेसी लिंक के अंतर्गत जल अनुप्रयोग से पुनरुद्भव का उपयोग संबंधित राज्य द्वारा किया जा सकता है।
- 1.8 जल बंटवारे, नियोजित उपयोग और पर्यावरणीय प्रवाह के सम्बन्ध में हुए अंतर्राज्यीय समझ के आधार पर, सीडब्ल्यूसी द्वारा विभिन्न स्थानों पर यथा आकलित सकल जल उपलब्धता और रा.ज.वि.अ द्वारा विभिन्न स्थानों/ डाइवर्जन बिन्दुओं पर आकलित नेट जल उपलब्धता **अनुलग्नक-II** में दी गई है। दोनों राज्य लिंक परियोजना के अंतर्गत विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल

dependability at these project locations. The equal quantum of water so utilized by Madhya Pradesh through five projects in Upper Chambal, shall be ensured and transferred from Kalisindh sub-basin to Gandhisagar reservoir at more than 75 percent success rate on substitution basis. The capital cost of entire water transfer system including barrage, pumping station and water conveyance system from Kalisindh sub-basin to Gandhisagar reservoir, shall be part of the Modified PKC Link Project. The O&M cost of water transfer from Kalisindh to Gandhisagar reservoir including power cost shall be borne by Madhya Pradesh. The five projects of Madhya Pradesh in Upper Chambal shall be operated only after the system for diversion of water from Kalisindh to Gandhisagar is in place so that the benefits from the existing Chambal Valley Development Project are not affected in both the States. The exchange of water in Upper Chambal basin and Kalisindh sub-basin shall be reviewed after completion of projects in Upper Chambal basin and subsequently every five years, in consultation with CWC. The barrage at Kalisindh river and water conductor system for diversion of water from Kalisindh to Gandhisagar shall be operated and maintained by the institution to be created for control mechanism, water accounting and regulation of water in Chambal basin.

- 1.6** While assessing the net water availability at any project location of Modified PKC link, apart from considering the requirements of existing, ongoing and contemplated projects, upstream or downstream of project location of each State in its territory, the provision for 10 percent of monsoon yield at 75% dependability and 100 percent of non-monsoon natural yield at that location shall be reserved by both the States for environment flows.
- 1.7** The regeneration from water application under the Modified PKC link can be utilized by the respective State.
- 1.8** The gross water availability as assessed by CWC at various locations and net water availability as assessed by NWDA at various locations/diversion points based on inter-State understanding on water sharing, planned utilization

उपयोग के द्वारा अपने क्षेत्र में पुनर्जनित जल का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

2.0 संशोधित पीकेसी लिंक के घटक

संशोधित पीकेसी लिंक के घटक, जिनमें हेड वर्क्स, दबावयुक्त पाइप वितरण नेटवर्क, पथांतरण प्रणाली और संतुलन जलाशय पंपिंग सिस्टम शामिल हैं, निम्नानुसार हैं:

2.1 मध्य प्रदेश राज्य को लाभान्वित करने वाले घटक-:

समूह क : कूनो उप-बेसिन में एसएमआरएस कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत परियोजनाएं

केयूएमपी 1 : धनवाड़ी सिंचाई परियोजना;

केयूएमपी 2 : नैनागढ़ सिंचाई परियोजना;

केयूएमपी 3 : सोनपुरा सिंचाई परियोजना;

केयूएमपी 4 : पावा सिंचाई परियोजना;

केयूएमपी 5 : श्यामपुर सिंचाई परियोजना;

केयूएमपी 6 : कटीला सिंचाई परियोजना;

समूह ख : पार्वती उप-बेसिन में परियोजनाएं

पीएमपी1 : कुंभराज-I सिंचाई परियोजना;

पीएमपी2 : कुंभराज-II सिंचाई परियोजना;

पीएमपी3 : पैडोन-I सिंचाई परियोजना;

पीएमपी4 : पैडोन-II सिंचाई परियोजना;

पीएमपी5 : श्यामपुर बैराज सिंचाई परियोजना;

पीएमपी6 : करिया बैराज सिंचाई परियोजना;

पीएमपी7 : जेठाला बैराज सिंचाई परियोजना;

समूह ग : कालीसिंध उप-बेसिन में परियोजनाएं

केएसएमपी1 : लखुंदर बैराज सिंचाई परियोजना (संतुलन जलाशयों सहित);

केएसएमपी2 : रणजीत सागर सिंचाई परिसर (संतुलन जलाशयों सहित);

केएसएमपी3 : कालीसिंध पथांतरणप्रणाली;

समूह घ : ऊपरी चंबल उप-बेसिन में परियोजनाएं

यूसीएमपी1 : चिताबद कॉम्प्लेक्स सिंचाई परियोजना;

and reservations for environmental flows are enclosed at **Annexure-II**. Both the States shall be free to utilise the regenerated water in their territory on account of water utilisation for various purposes under the link project.

2.0 COMPONENTS OF THE MODIFIED PKC LINK

The components of the modified PKC link, including head works, pressurized pipe distribution network, diversion system and balancing reservoir pumping system are as per the following:-

2.1 Components Benefitting the State of Madhya Pradesh:-

Group A : Projects under SMRS Complex in Kuno Sub-basin

- KUMP1 : Dhanwadi Irrigation Project;
- KUMP2 : Nainagarh Irrigation Project;
- KUMP3 : Sonpura Irrigation Project;
- KUMP4 : Pawa Irrigation Project;
- KUMP5 : Shyampur Irrigation Project;
- KUMP6 : Kateela Irrigation Project;

Group B : Projects in Parbati Sub-basin

- PAMP1 : Kumbhraj-I Irrigation Project;
- PAMP2 : Kumbhraj-II Irrigation Project;
- PAMP3 : Padone-I Irrigation Project;
- PAMP4 : Padone-II Irrigation Project;
- PAMP5 : Shyampur Barrage Irrigation Project;
- PAMP6 : Kariya Barrage Irrigation Project;
- PAMP7 : Jethala Barrage Irrigation Project;

Group C : Projects in Kalisindh Sub-basin

- KSMP1 : Lakhundar Barrage Irrigation Project including balancing reservoirs ;
- KSMP2 : Ranjit Sagar Irrigation Complex including balancing reservoirs ;
- KSMP3 : Kalisindh Diversion System;

- यूसीएमपी2 : सोनचिरी बांध;
 यूसीएमपी3 : सीकारी-सुल्तानपुर बांध;
 यूसीएमपी4 : सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी सिंचाई परियोजना;
 यूसीएमपी5 : मल्हारगढ़-शिवना सिंचाई परियोजना;

2.2 राजस्थान राज्य को लाभान्वित करने वाले घटक:-

समूह ड : ईआरसीपी परियोजना

- ईआरसीपी1 : कुल नदी पर रामगढ़ बैराज;
 ईआरसीपी2 : पार्वती नदी पर महलपुर बैराज;
 ईआरसीपी3 : कालीसिंध नदी पर नवनेरा बैराज;
 ईआरसीपी4 : मेज नदी पर मेज बैराज;
 ईआरसीपी5 : बनास नदी पर नीमोद राठौड़ बैराज (संतुलन जलाशय);
 ईआरसीपी6 : बीसलपुर बांध की भंडारण क्षमता बढ़ाना (ऊंचाई 0.5 मीटर बढ़ाकर);
 ईआरसीपी7 : बनास नदी पर इशारदा बांध;
 ईआरसीपी8 : बनास नदी पर डूंगरी बांध (संतुलन जलाशय);
 ईआरसीपी9 : रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध और गलवा बांध तक जल संवाहक प्रणाली तथा आगे बीसलपुर बांध, इशारदा बांध, रामगढ़ बांध-जयपुर, मोर सागर-अजमेर, अलवर जलाशय, बंड बरेठा, उर्मिला सागर तक जल संवाहक प्रणाली तथा कमांड में सूक्ष्म सिंचाई नेटवर्क का विकास;
 ईआरसीपी10 एमपीकेसी (ईआरसीपी) के विभिन्न संरक्षण बिंदुओं के साथ मौजूदा मार्गस्थ तालाबों का नवीनीकरण और एकीकरण और कमान में सूक्ष्म सिंचाई नेटवर्क का विकास;
 ईआरसीपी11 : अजमेर में मोर सागर कृत्रिम संतुलन जलाशय;
 ईआरसीपी12 : अलवर में कृत्रिम संतुलन जलाशय;

समूह च : कूनो उप-बेसिन में परियोजनाएं

- केयूआरजे1 : 9 सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के क्लस्टर को लागू करके कूनो उप-बेसिन में कमांड विकसित करना;

Group D : Projects in Upper Chambal Sub-basin

- UCMP1 : Chitabad Complex Irrigation Project;
UCMP2 : Sonchiri Dam;
UCMP3 : Sikari-Sultanpur Dam;
UCMP4 : Sewarkheri-Silarkhedi Irrigation Project;
UCMP5 : Malhargarh-Shivna Irrigation Project;

2.2 Components Benefitting State of Rajasthan:-

Group E : Projects ERCP

- ERCP1 : Ramgarh Barrage on Kul River;
ERCP2 : Mahalpur Barrage on Parbati river;
ERCP3 : Navnera Barrage on Kalisindh river;
ERCP4 : Mej Barrage on Mej river;
ERCP5 : Neemod Rathod Barrage (Balancing reservoir) across Banas river;
ERCP6 : Enhancing storage capacity of Bisalpur dam by raising 0.5 m;
ERCP7 : Isarda Dam across Banas River;
ERCP8 : Doongri Dam (balancing reservoir) across Banas river;
ERCP9 : Water conductor system from Ramgarh Barrage to Doongri Dam & Galwa Dam and further to Bisalpur Dam, Isarda Dam, Ramgarh Dam-Jaipur, Mor Sagar- Ajmer, Alwar Reservoir, Bund Baretha, Urmila Sagar and development of micro irrigation network in the command;
ERCP10 : Renovation and integration of existing en-route tanks with various conservation points of MPKC (ERCP) and development of micro irrigation network in the command;
ERCP11 : Mor Sagar Artificial Balancing Reservoir in Ajmer;
ERCP12 : Artificial Balancing Reservoir in Alwar;

Group F : Projects in Kuno Sub-basin

- KURJ 1 : Developing command in Kuno sub basin by implementing cluster of 9 Micro Irrigation Schemes;

समूह छ : पार्वती उप-बेसिन में परियोजनाएं

पीएआरजे1 : अंधेरी बांध सिंचाई परियोजना;

पीएआरजे2 : सुकनी (नदी) जलाशय (रैखिक जलाशय);

समूह ज : कालीसिंध उप-बेसिन में परियोजनाएं

केएआरजे1 : कालीसिंध नदी पर हरिपुरा बैराज;

केएआरजे2 : झालावाड़ में मोरी कृत्रिम जलाशय;

केएआरजे3 : झालावाड़ में सोयला कृत्रिम जलाशय;

केएआरजे4 : कोटा में पाटली नदी पर पाटली प्रथम बांध;

केएआरजे5 : कोटा में पाटली नदी पर पाटली द्वितीय बांध;

केएआरजे6 : मनोहरथाना सिंचाई परियोजनाएं;

केएआरजे7 : झालावाड़ जिले में दाब सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए 33 डब्ल्यूएचएसका क्लस्टर;

2.3 संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना चंबल बेसिन के उप-बेसिनों में उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर और आर्थिक रूप से उपयोग करने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य पीपीपी अथवा किसी अन्य उपयुक्त मॉडल पर उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाकर सतत अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के अवसरों का पता लगा सकते हैं ताकि एमपीकेसी को हरित परियोजना बनाया जा सके।

3.0 लागत का बंटवारा

3.1 संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना को केंद्र से वित्तीय सहायता के साथ नदी को जोड़ने की राष्ट्रीय परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण पैटर्न का निर्णय पीआईबी और कैबिनेट द्वारा अनुमोदन के अनुसार किया जाएगा। प्रत्येक राज्य अपने-अपने घटकों केलागत का राज्य अंश वहन करेगा।

3.2 संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना के पूरा होने पर, प्रचालन एवं ओ एंड एम लागत पूरी तरह से राज्यों द्वारा उनके संबंधित घटकों के लिए वहन की जाएगी। चंबल बेसिन में जल के लेखांकन और विनियमन के लिए इस परियोजना के लिए स्थापित की जाने वाली संस्थागत व्यवस्था की संचालन लागत दोनों राज्यों द्वारा समान रूप से वहन की जाएगी।

Group G : Projects in Parbati Sub-basin

PARJ1 : Andheri Dam Irrigation Project;

PARJ2 : Sukani (River) Reservoir (Linear Reservoir);

Group H : Projects in Kalisindh Sub-basin

KARJ1 : Haripura Barrage on Kalisindh river;

KARJ2 : Mori Artificial Reservoir in Jhalawar;

KARJ3 : Soyla Artificial Reservoir in Jhalawar;

KARJ4 : Patli Ist Dam on Patli River in Kota;

KARJ5 : Patli IInd Dam on Patli River in Kota;

KARJ6 : Manoharthana Irrigation Project;

KARJ7 : Cluster of 33 nos. WHS for providing pressure
Irrigation in Jhalawar District;

- 2.3 The Modified PKC link project will help in utilizing the available water resources in the sub-basins of Chambal basin optimally and economically. Further, States may explore opportunities for generation of sustainable renewable energy on PPP or any other suitable model by leveraging available resources so as to make MPKC as a green project.

3.0 SHARING OF COST

- 3.1 The Modified PKC Link Project shall be implemented as a National Interlinking of River Project with financial support from the Centre. The funding pattern between the Centre and States shall be decided on approval by PIB and Cabinet. Each State shall bear the State share of components of respective State.
- 3.2 On completion of Modified PKC Link Project, the O&M cost shall be borne entirely by the States for their respective components. The running cost of the institutional arrangement to be established for this project, for the accounting and regulation of water in the Chambal basin shall be borne by both the States equally.

4.0 कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र

4.1 दोनों राज्य अपने संबंधित घटकों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित सांविधिक मंजूरी लेने के बाद समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। मूल्यांकन और अपेक्षित स्वीकृतियां सभी घटकों (उपर्युक्त खंड 2.0 के अनुसार) के लिए समग्र रूप से एक साथ या चरणों में ली जा सकती हैं।

4.2 लिंक परियोजना की योजना, वित्तीय चरणबद्धता, निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण के कार्यान्वयन के लिए दोनों राज्यों की भागीदारी से, केन्द्र द्वारा एक निगरानी प्रकोष्ठ सृजित किया जाएगा। निगरानी प्रकोष्ठ की परिचालन लागत, लिंक परियोजना की स्थापना लागत से ली जाएगी और अनुमोदित वित्त पोषण पैटर्न पर केंद्र और दोनों राज्यों द्वारा साझा की जाएगी।

5.0 परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वासन और पुनर्स्थापन

परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वासन और पुनर्स्थापन तथा उनके क्षेत्रीय अधिकार के भीतर परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" के अनुसार या संबंधित राज्य नीति और अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।

6.0 विवाद समाधान तंत्र

सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग), भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित एक संचालन समिति, जिसमें दोनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, समय-समय पर नीतियों, प्रगति, वित्त पोषण और अन्य संबंधित मामलों सहित परियोजना के समग्र कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी। कार्यान्वयन के स्तर पर उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे का समाधान, संचालन समिति द्वारा किया जाएगा। संचालन समिति स्तर पर उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को केंद्रीय मंत्री (जल शक्ति) की

4.0 IMPLEMENTATION AND MONITORING MECHANISM

4.1 Both the States shall be responsible for the implementation of their respective components in a time bound manner after taking requisite statutory clearances for their implementation. The appraisal and requisite clearances may be taken as whole for all components together or in phases for components specified in each group as per clause 2.0 above.

4.2 A Monitoring Cell shall be created by the Centre with the participation of both the States for implementation of planning, financial phasing, monitoring and quality control of the link project. The running cost of the Monitoring Cell shall be charged towards the establishment cost of the link project and shall be shared by Centre and both the States on the approved funding pattern.

5.0 REHABILITATION AND RESETTLEMENT (R & R) OF PROJECT AFFECTED FAMILIES (PAFS)

Rehabilitation and Resettlement of project affected families and land acquisition for the projects within their territorial jurisdiction would be carried out by the respective State Governments in a time bound and transparent manner as per “The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013” or as per the respective State Policy and as per approved Environmental Management Plan.

6.0 DISPUTE RESOLUTION MECHANISM

A **Steering Committee** headed by Secretary (DoWR,RD&GR), Govt. of India with representations from both the State Governments shall periodically review the overall implementation of the project including policies, progress, funding and other related matters. Any issue arising at implementation stage shall be resolved by the Steering Committee. Any dispute arising at Steering

अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति को भेजा जाएगा, जिसमें दोनों राज्यों के जल संसाधन/जल शक्ति मंत्री शामिल होंगे।

05 दिसम्बर, 2024 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित।

(डॉ. मोहन यादव)

मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश राज्य के लिए

(भजन लाल शर्मा)

मुख्यमंत्री, राजस्थान
राजस्थान राज्य के लिए

(सी. आर. पाटिल)

जल शक्ति मंत्री
संघ सरकार के लिए

Committee level shall be referred to **High Level Committee** headed by Union Minister (Jal Shakti) and comprising of the Water Resources/Jal Shakti Ministers of both the States.

Signed at New Delhi on this day of 5th December, 2024

(DR. MOHAN YADAV)
Chief Minister of Madhya Pradesh
FOR THE STATE OF
MADHYA PRADESH

(BHAJAN LAL SHARMA)
Chief Minister of Rajasthan
FOR THE STATE OF
RAJASTHAN

(CR PATIL)
Minister for Jal Shakti
FOR THE UNION GOVERNMENT

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

राजस्थान राज्य, मध्य प्रदेश राज्य

और

संघ सरकार के बीच में

संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

amongst

THE STATE OF RAJASTHAN,

THE STATE OF MADHYA PRADESH

and

THE UNION GOVERNMENT

on

**MODIFIED PARBATI-KALISINDH-CHAMBAL
LINK PROJECT**

28th January, 2024

New Delhi

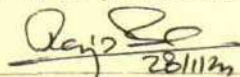
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) AMONGST THE STATE OF RAJASTHAN, THE STATE OF MADHYA PRADESH AND THE UNION GOVERNMENT ON MODIFIED PARBATI-KALISINDH-CHAMBAL LINK PROJECT.

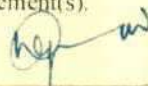
Name & Address of Parties

1. Government of Rajasthan, Water Resources Department, Jaipur.
2. Government of Madhya Pradesh, Water Resources Department, Vallabh Bhawan, Bhopal.
3. Union Government, Ministry of Jal Shakti, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.

I. Introduction

- A. WHEREAS the Government of India considers the programme for inter linking of rivers as of national importance and shall work out to find out/suggest modalities for project funding mechanism so as to enable to complete the project within the stipulated time frame.
- B. WHEREAS the Government of India, in consultation with the States, shall develop a plan for interlinking of rivers of Chambal basin including the integration of Eastern Rajasthan Canal Project for optimum utilisation of water resources in the basin. This link named as the Modified Parbati-Kalisindh-Chambal Link, shall be part of the National Perspective Plan(NPP) of interlinking of rivers in the country, as approved by Special Committee for Interlinking of Rivers (SCILR) in its 20th meeting held on 13th December, 2022.
- C. WHEREAS, the Detailed Project Report of the Modified PKC link shall be prepared jointly by National Water Development Agency (NWDA) and both the states expeditiously as per prevailing guidelines.
- D. AND WHEREAS the Union Government, in consultation with the States will create an appropriate mechanism for implementation of the Modified Parbati-Kalisindh-Chambal Link as appropriate. Govt. of India in consultation with the States will also create an appropriate body for water accounting and allocation of water as per water sharing agreement(s).


28/11/22





II. Background

1. The Feasibility Report (FR) of Parbati-Kalisindh-Chambal (PKC) link project under National Perspective Plan (NPP) (Technical Study No. FR(P)/9/04) was prepared and circulated amongst the members of TAC and to the concerned State Governments in February-2004. The PKC link project could not be materialized because the consensus on water sharing could not reach between Madhya Pradesh and Rajasthan.
2. With a view to utilise the water resources optimally, the integration of the Parbati-Kalisindh-Chambal (PKC) link of NPP with Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP) was discussed in 11th and 12th meeting of the Task Force for Interlinking of Rivers (TFILR). Thereafter, the issue of integration of ERCP with PKC link has been deliberated regularly with states at various platforms.
3. Looking at the importance and utility of the Modified PKC link project, Special Committee for Interlinking of Rivers (SCILR), in its 20th meeting held on 13.12.2022 in New Delhi has approved the Modified PKC link as the part of the National Perspective Plan of Interlinking of rivers in the country and also declared it as one of the priority link projects in the country.

III. NOW, THEREFORE IT IS HEREBY MUTUALLY UNDERSTOOD BY THE PARTIES AS FOLLOWS:

1.0 Water Sharing in Modified PKC link project

- 1.1 The water sharing in the Modified Parbati-Kalisindh-Chambal link duly integrated with ERCP shall be determined by the understanding reached between two states in the Control Board and guidelines for planning of water resources projects of Ministry of Jal Shakti.
- 1.2 Specific MoA as required shall be entered later amongst the States of Rajasthan, Madhya Pradesh and Union Government based on the outcome of the DPR of Modified Parbati-Kalisindh-Chambal link duly integrated with Eastern

   21

Rajasthan Canal Project, covering scope of the work of the Project, sharing of water, exchange of water, sharing of costs & benefits, implementation mechanism and arrangements for management and control of water etc.

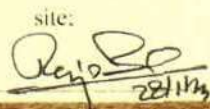
- 1.3 Under the Modified PKC link, there shall be equal exchange of water in Kuno and Parbati between two states. There shall be equal exchange of water in Kalisindh and Upper Chambal basin based on detailed hydrology and without affecting the Chambal Valley Development Project in both the states.
- 1.4 Under the system, both the states shall be allowed to use the water availability as per Guidelines for preparation of DPRs of Irrigation and Multipurpose Projects, Govt. of India, Ministry of Water Resources, 2010 and Niti Aayog norms for planning of irrigation projects in inter-states rivers. However, the states can harness more water of Kalisindh sub-basin as well as such other tributaries of the Chambal river as per demands assessed based on applicable norms and optimum utilization of water resources, as mutually agreed by both the states.
- 1.5 While assessing the net water availability at any project location of Modified PKC link, apart from considering the requirements of existing, ongoing and contemplated projects in U/S or d/s commitments, if any, the provision for 10 percent of monsoon yield and 100 percent of non-monsoon natural yield at that location shall be reserved for environment flows.

2.0 Components of Modified PKC Link

2.1 Modified PKC Link proposal broadly includes:

2.1.1 Components Benefitting the State of Madhya Pradesh:-

- a) A dam proposed at Kumbhraj across Parbati river;
- b) Dams proposed across Kuno river and its tributaries;
- c) Lakhunder Barrage across Lakhunder river in Kalisindh to divert water to Kundaliya dam and Ranjit Sagar dam proposed upstream of Kundaliya dam site;


28/1/13



 31

d) Transfer of water from Kalisindh sub-basin to Gandhisagar reservoir or upper Chambal sub-basin and its equivalent utilisation in Upper Chambal basin through seven projects namely Sonechiri, Ramwasa, Bachora, Padunia, Sewarkheri, Sekri and Sultanpura;

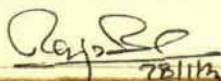
2.1.2 Components Benefitting State of Rajasthan :-

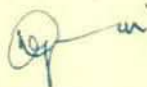
- a) Ramgarh Barrage on Kul River;
- b) Mahalpur Barrage on Parbati river;
- c) Navnera Barrage on Kalisindh river;
- d) Mej Barrage on Mej river;
- e) Rathod Barrage on Banas river;
- f) Doongri Dam across Banas river;
- g) Water conductor system from Ramgarh barrage to Doongri dam;
- h) Renovations and Integration of Isarda dam and 26 nos. of tanks (existing) with various conservation points of ERCP.

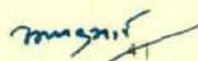
This link project proposes to provide drinking and industrial water in 13 districts of eastern Rajasthan, Malwa and Chambal regions of Madhya Pradesh apart from providing irrigation in 2.8 lakh ha. area or more each in both the states including supplementation of en- route tanks in the states.

The Modified PKC link project will help in utilizing the available water resources of Chambal basin optimally and economically. The various components of Modified PKC link including areas of benefit shall be firmed up at DPR stage in consultation with both the states.

- 2.2** The preparation of DPR of Modified Parbati-Kalisindh-Chambal link shall be taken up jointly by both the states and National Water Development Agency. Both the States shall extend full cooperation in preparation and finalisation of the DPR expeditiously. The Hydrology of all the projects shall be finalised by Central Water Commission.


28/1/13





Both the states of Madhya Pradesh and Rajasthan enter into Agreement with the Union Government for the planning and preparation of the DPR of the Modified PKC link project in the larger interest of utilising the waters of Chambal basin optimally and fulfil the irrigation and the drinking water needs in both the states.

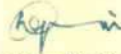
Signed at New Delhi on this day of 28th January, 2024


(Dr. Rajesh Kumar)

(ACS, WRD, Govt. of Madhya Pradesh)


(Abhay Kumar)

(ACS, WRD, Govt. of Rajasthan)



(Debashree Mukherjee)

Secretary, DoWR, RD&GR,

Ministry of Jal Shakti, Govt. of India

Assessment of Water Availability for MPKC Link Project

Annexure-II/अनुलग्नक-II #

(Water data in MCM)

S.No.	Diversion Sites	States	Dependability %	Gross Annual Yield	Total Planned Utilisation	E-Flow	Total Regeneration	10% Virgin yield from MP catchment	Water balance	Net Water available in MPKC	Remarks
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)=A-B-C+D+E	(G)	
1.	Upto Mahalpur on Parbati	MP	75	2320.2	1181.8	330.5	241.6	-182.97	866.53	750.53	G = F - 116*
		RAJ	75	672.2	311.7	95.8	43.9	182.97	491.57	607.57	G = F + 116*
2.	SMRS (upto Shyampur) on Kuno river	MP	75	752.3	121.5	107	60	0	583.8	699.80	G = F + 116*
		RAJ	75	176.7	11.4	25.2	3.2	0	143.3	27.30	G = F - 116*
3.	Ramgarh on Kul river	MP	75	0	0	0	0	0	0	0	
		RAJ	75	215.3	126.6	30.7	7.8	0	65.8	65.80	
4.	Navnera on Kalisindh	MP	50	4003.2	2203	323.4	412.8	-257	1632.6	1632.60	
		RAJ	50	2458.8	1127.8	207.1	322	257	1702.9	1702.90	
5.	Mej Barrage on Mej river	MP	50	0	0	0	0	0	0	0	
		RAJ	50	447.2	272.8	41.4	68.7	0	201.7	201.70	

S.No.	Diversion Sites	States	Dependability %	Gross Annual Yield	Total Planned Utilisation	E-Flow	Total Regeneration	10% Virgin yield from MP catchment	Water balance	Net Water available in MPKC	Remarks
6.	Isarda on Banas river	MP	50	0	0	0	0	0	0	0	
		RAJ	50	1021.7	292.3	99.5	15.3	0	645.2	645.20	
7.	Rathod on Banas river	MP	50	0	0	0	0	0	0	0	
		RAJ	50	79.9	30.91	7.2	2.2	0	44.0	44.00	
8.	Doongri on Banas River	MP	50	0	0	0	0	0	0	0	
		RAJ	50	516.6	331.9	71.8	27.4	0	140.3	140.30	
9.	CA lying between Mahalpur & Navnera	MP	75	0	0	0	0	0	0	0	
		RAJ	75	168.4	0	22.6	0	0	145.8	145.80	
(a) Water available for MP									3082.93		
(b) Regeneration from Water Utilization under MPKC (MP Part)									37.16		
Total Water Available for MP								(a+b)	3120.09		
(c) Water available for Rajasthan									3580.60		
(d) Regeneration from Water Utilization under MPKC (Rajasthan Part)									522.00		
Total Water Available for Rajasthan								(c+d)	4102.60		

Note: (*) indicates quantum of water to be exchanged by MP and Rajasthan in Kuno and Parbati sub-basins on substitution basis.

(#) The table shown as Annexure-II has been concurred by Govt. of MP and Govt. of Rajasthan for their part vide their letter no. 3741062/अ ज स ई /2016/ पीकेसी पत्राचार dated 10.10.2024 and F.4(28)/ERCP/T/MPKC-MoA/2024/1732 dated 08.10.2024 respectively.

Details of Components in Modified PKC Link Project**I. Components Benefitting the State of Madhya Pradesh:**

Sl. No	Projects	Location	Catchment Area (Sq. Km)	Height of structures (m)	Live Storage capacity (MCM)	Planned Utilisation (MCM)			Total Utilisation	Annual Irrigation (ha)
						Irrigation requirement	Requirement for Power/ Industries	Drinking Water		
Group-A: Projects under SMRS Complex in Kuno Sub- Basin										
1.	KUMPI : Dhanwadi Irrigation Project	Guna	220.80	36.80	44.35	41.35	1	2	44.35	12660
2.	KUMP2 : Nainagarh Irrigation Project	Guna	499.19	17.825	36.38	34.38	1	1	36.38	17100
3.	KUMP3 : Sonpura Irrigation Project	Shivpuri	378.37	31.0	69.29	65.29	1	3	69.29	19860
4.	KUMP4: Pawa Irrigation Project	Shivpuri	386.345	40.0	40.98	37.98	1	2	40.98	11450
5.	KUMP5: Shyampur Irrigation Project	Sheopur	4318.12	27.00	78.12	78.12	0	0	78.12	27000
6.	KUMP6: Kateela Irrigation Project	Shivpuri	3206.50	31.50	350.36	317.86	17.50	15	350.36	100000
Group-B: Projects in Parbati Sub-basin										
7.	PAMP1 : Kumbhraj-I Irrigation Project	Guna	5927	38	368.88	333.30	0	35.58	368.88	105000

Sl. No	Projects	Location	Catchment Area (Sq. Km)	Height of structures (m)	Live Storage capacity (MCM)	Planned Utilisation (MCM)			Total Utilisation	Annual Irrigation (ha)
						Irrigation requirement	Requirement for Power/ Industries	Drinking Water		
8.	PAMP2 : Kumbhraj-II Irrigation Project	Guna	6458	16	41.60	41.60	0	0	41.60	12480
9.	PAMP3 : Padone-I Irrigation Project	Guna	267.23	25	50.77	50	0	0.77	50.77	15000
10.	PAMP4 : Padone-II Irrigation Project	Guna	290.25	18	20.64	20	0	0.64	20.64	6000
11.	PAMP5 : Shyampur Barrage Irrigation Project	Sehore	2013	24.50	35.30	30.15	0	2.50	32.65	9273
12.	PAMP6 : Kariya Barrage Irrigation Project.	Sehore	1806	25	35.59	30	0	2.50	32.50	9227
13.	PAMP7 : Jethala Barrage Irrigation Project	Sehore	3302	26.32	101	94.29	0	1	95.29	29000
Group-C: Projects in Kalisindh Sub-basin										
14.	KSMP1 : Lakhundar Barrage plus BRs Irrigation Project	Shajapur	880	-	174.45	67.82	0	4.50	72.33	25000

Sl. No	Projects	Location	Catchment Area (Sq. Km)	Height of structures (m)	Live Storage capacity (MCM)	Planned Utilisation (MCM)			Total Utilisation	Annual Irrigation (ha)
						Irrigation requirement	Requirement for Power/ Industries	Drinking Water		
15.	KSMP2 : Ranjit Sagar complex plus BRs Irrigation Project	Shajapur/ Dewas	3188	-	148.44	136.25	0	0.90	137.15	50500
16.	KSMP3: Kalisindh Diversion System	Rajgarh	5953	23.55	70	450 MCM water proposed to be diverted during monsoon to Gandhisagar			-	-
Group-D: Projects in Upper Chambal Sub-basin										
17.	UCMP1: Chitabad Complex Irrigation project	Ujjain	4449.10	23.02	160	160	0	0	160	65000
18.	UCMP2 : Sonchiri Dam	Ujjain	1427	23.10	24.57	24.57	0	0	24.57	7800
19.	UCMP3 : Sikari-Sultanpur Dam	Ujjain	1967	19.50	31.57	31.57	0	0	31.57	9900
20.	UCMP4: Sewarkheri-Silarkhedi Irrigation Project	Ujjain	1045	25.19	52.45	51	0	0	51	18800
21.	UCMP5: Malhargarh – Shivna Irrigation Project	Mandsaur	1610	48	175.10	170.40	0	0	170.40	60000
Total for MP					2109.84	1815.93	21.50	71.39	1908.83	6,11,050

II. Components Benefitting the State of Rajasthan

Sl. No	Projects	Location	Catchment Area (Sq. Km)	Height of structures (m)	Live Storage capacity (MCM)	Planned Utilisation (MCM)			Total Utilisation	Annual Irrigation (ha)
						Irrigation requirement	Requirement for Power/ Industries	Drinking Water		
Group-E: Projects ERCP										
1.	ERCP-1: Ramgarh Barrage	Baran, Kishanganj	986	37	39.92	0	0	3.90	3.90	0
2.	ERCP-2: Mahalpur Barrage	Baran, Kishanganj	11835	42	228.41	0	10	7.54	17.54	0
3.	ERCP-3: Navnera Barrage	Jhalrapata, Jhalawar	24668	44	196.22	2.29	10	69.99	82.28	800
4.	ERCP-4: Mej Barrage	Indargarh, Bundi	5830	28	102.16	87.14	2	7.03	96.17	30500
5.	ERCP-5: Neemod Rathod Barrage	Sawai Madhopur	44732	17	200	14.29	5	15.62	34.91	5000
6.	ERCP-6 Enhancing storage capacity of Bisalpur dam by raising 0.5 m ht	Deoli, Tonk	27726	40	1194*	0	0	870.11	870.11	-
7.	ERCP-7: Isarda Dam	Uniara, Tonk	43739	31	290	0	0	386.74	386.74	0

Sl. No	Projects	Location	Catchment Area (Sq. Km)	Height of structures (m)	Live Storage capacity (MCM)	Planned Utilisation (MCM)			Total Utilisation	Annual Irrigation (ha)
						Irrigation requirement	Requirement for Power/ Industries	Drinking Water		
8.	ERCP-8: Doongri Dam	Sawai Madhopur	53307	53.50	1588	397.33	5	60.93	463.26	119200
9.	<p>ERCP-9 : Water conductor system from Ramgarh Barrage to Doongari Dam & Galwa Dam and further to Bisalpur Dam, Isarda Dam, Ramgarh Dam-Jaipur, Mor Sagar- Ajmer, Alwar Reservoir, Bund Baretha, Urmila Sagar and development of micro irrigation network in the command.</p> <p>This consists of gravity canal (752 km.), Tunnels (19 km.), natural streams (100 km.) and pipeline (pressure flow) of 193 km. Thus the total length of water conductor system is 1064 km. approx.</p>									
	<p>ERCP-10 Renovation and integration of existing en-route tanks with various conservation points of MPKC (ERCP) and development of micro irrigation network in the command.</p> <p>This component covers the stabilization of command area 1.52 lakh ha. through 138 tanks utilizing 615 MCM water. There are other 20 water bodies for ground water recharge and livestock by 29 MCM water. There is also provision for drinking and power/industries as 96 MCM and 12 MCM respectively.</p>					644	12	96	752	152400
11.	ERCP-11: Mor Sagar Artificial Balancing Reservoir	Ajmer	-	41	190	0	9	91	100	0

Sl. No	Projects	Location	Catchment Area (Sq. Km)	Height of structures (m)	Live Storage capacity (MCM)	Planned Utilisation (MCM)			Total Utilisation	Annual Irrigation (ha)
						Irrigation requirement	Requirement for Power/ Industries	Drinking Water		
12.	ERCP-12: Artificial Balancing Reservoir	Alwar	-	46	300	0	123.50	104	227.50	0
Group-F: Projects in Kuno Sub-basin										
13.	KURJ-1: Developing command in Kuno sub basin by implementing cluster of 9 Micro Irrigation Schemes				27.31	20	7.31	0	27.31	7000
Group-G: Projects in Parbati Sub-basin										
14.	PARJ-1: Andheri Medium Irrigation Project	Baran	304.87	23.30	37.28	37.28	0	0	37.28	9850
15.	PARJ-2 : CA lying between Mahalpur & Navnera (Sukani River Reservoir)	Kota, Pipalda (Linear Reservoir)	482	5	44.4	11.43	0	0	11.43	4000
Group-H: Projects in Kalisindh Sub-basin										
16.	KARJ-1: Haripura barrage	Kota	5590	27	63.80	41.86	21.94	0	63.80	15000

Sl. No	Projects	Location	Catchment Area (Sq. Km)	Height of structures (m)	Live Storage capacity (MCM)	Planned Utilisation (MCM)			Total Utilisation	Annual Irrigation (ha)
						Irrigation requirement	Requirement for Power/ Industries	Drinking Water		
17.	KARJ-2: Mori artificial reservoir (water to be transferred from kalisindh dam)	Jhalawar	0	20	18	0	0	18	18.00	0
18.	KARJ-3: Soyala artificial reservoir (water to be transferred from kalisindh dam)	Jhalawar	0	22	32.15	28.57	0	0	28.57	10000
19.	KARJ-4: Patli -I dam on patli river of kalisindh basin	Ramganj Mandi	257.70	19.20	10.95	10.86	0	0	10.86	3800
20.	KARJ-5: Patli -II dam on patli river	Ramganj Mandi	257.70	16.70	6.68	6.29	0	0	6.29	2200
21.	KARJ-6: Manoharthana Medium Irrigation Project	Jhalawar	1176	27.20	59	45.75	0	13.25	59.00	9834
22.	KARJ-7: Cluster of 33 nos. WHS for providing pressure Irrigation in Jhalawar District				14.2	12.88	0	0	12.88	4508
Total for Rajasthan					4642.48	1359.97	205.75	1744.16	3309.83	403652**

(*) Live storage capacity of existing Bisalpur dam is being enhanced by 99 MCM, so as to increase the live storage from existing 1095 MCM to 1194 MCM.

(**) Includes the CCA 29560 ha. from regenerated water.

(##) The table shown as Annexure-III has been concurred by Govt. of MP and Govt. of Rajasthan for their part vide their letters no. 3741062/ अ ज स ई / 2016/पीकेसी पत्राचार dated 10.10.2024 and F.4(28)/ERCP/T/MPKC-MoA/2024/1732 dated 08.10.2024 respectively.

Benefitted districts of MP: Shivpuri, Gwalior, Bhind, Morena, Sheopur, Shajapur, Agar Malwa, Rajgarh, Sehore, Guna, Ratlam, Mandsaur, Ujjain, Dhar and Dewas including Malwa region.

Benefitted districts of Rajasthan: Jhalawar, Baran, Kota, Bundi, Tonk, Sawai Madhopur, Gangapur city, Dausa, Karauli, Dholpur, Bharatpur, Deeg, Alwar, Khairthal-Tijara, Kotputali - Behror, Jaipur urban, Jaipur rural, Dudu, Ajmer, Beawar, Kekri.

MPKC LINK PROJECT SUMMARY

S.No.	State	Live Storage (MCM)	Planned Utilisation MCM			Annual Irrigation (ha)
			Irrigation	Industrial	Drinking Water	
1.	MP	2109.84	1815.93	21.50	71.39	611050
2.	Rajasthan	4642.48	1359.97	205.75	1744.16	403652
	Grand Total	6752.32	3175.90	227.25	1815.55	1014702

Note:- The MPKC link Project shall also include the Renovation/Modernisation of Right Main Canal and Left Main Canal of Kota barrage, as well as the installation of SCADA system on these canals.